



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 362]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 362]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

---

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 14 अक्टूबर, 2019

सं. टीएएमपी/24/2014-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणियों की दर संरचना की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

---

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10 वे दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा डीपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. डीपीटी की कांडला भूमि के पट्टा किराये पिछली बार 13 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा संशोधित किये गए। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टा किराये को 01 जनवरी, 2014 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया गया था और पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2018 तक की वैधता निर्धारित की गई थी। डीपीटी को हमारे 05

नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा दरों की अधिसूचना में विलंब से बचने के लिए डीपीटी भूमि के किरायों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीपीटी के अनुरोध पर डीपीटी की 'ए' से 'जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमियों की मौजूदा दर संरचना का पिछली बार विस्तार 29 मार्च 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा 30 जून, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था, जैसा डीपीटी ने चाहा था।

3.1. डीपीटी ने अपने 31 जुलाई, 2019 के पत्र के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मूल्यांकक से भू-मूल्यांकन रिपोर्ट मिल गई है और 1 जनवरी 2019 से दरों की वैधता को अंतिम रूप देने में थोड़ा और समय लगेगा। अतः उन्होंने मौजूदा दरों को और 6 महीने के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो 2% वृद्धि के साथ बढ़ा दिया जाए। डीपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना के संशोधन के लिए प्रस्तावित की जाने वाली संशोधित दरों पिछले संशोधन की समाप्ति की तारीख से या डीपीटी की कांडला भूमि की दर संशोधन की तारीख से अर्थात् 1 जनवरी, 2019 के पूर्ववर्ती प्रभाव से कार्यान्वित किया जायेगा।

उन्होंने यह भी बताया है कि, इस समय पट्टा धारकों को अंतरिम पट्टा किराया/ प्रतिपूर्ति बिल वर्ष 2018 के दौरान लागू दर पर 2% वार्षिक के साथ जारी किये जा रहे हैं।

3.2. उक्त स्थिति के अनुसार, डीपीटी ने इस प्राधिकरण को मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, तक 2% वृद्धि के साथ, विस्तार करने का अनुरोध किया है।

3.3. चूंकि कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी की दर संरचना की वैधता 30 जून 2019 को समाप्त हो गई है और इस संबंध में डीपीटी के अनुरोध को देखते हुए यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, विस्तार करता है, जैसा डीपीटी ने चाहा है।

3.4. डीपीटी को हमारे 14 अगस्त, 2019 के पत्र के द्वारा पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि वह 'ए' से 'जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमि की दर संरचना के संशोधन का प्रस्ताव 30 सितंबर, 2019 तक हर हाल में दायर कर दें। इसलिए डीपीटी यह निदेश दिया जाता है कि अपना प्रस्ताव निर्धारित तारीख तक दायर कर दें। डीपीटी से प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है।

4.1. सरकार द्वारा जारी भू-नीति दिशानिर्देश 2014 (जिसके आधार पर डीपीटी की कांडला भूमियों की 'ए से जी' श्रेणियों की दर संरचना नवंबर, 2014 में निर्धारित किये गए थे) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये तब तक 2% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ होंगे जब तक इस प्राधिकरण द्वारा उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2014 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में यह शर्त विशिष्ट रूप से दी गई है। यह एमओएस द्वारा जारी संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2014 में भी दी गई है। चूंकि वर्तमान दर संरचना का जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता तब तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी और 2% वार्षिक वृद्धि डीपीटी के 'ए से जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमि की दर संरचना में विस्तारित वैधता अवधि में भी लागू रहेगी।

4.2. तथापि, इस संबंध में यह भी नोट किया जाये कि वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान पट्टा किरायों का विस्तार एक अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर 'ए से जी' श्रेणी के लिए कांडला भूमि के लिए निर्धारित किये जाने वाले पट्टा किरायों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पड़ेगा, जैसा डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को उनकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसंबर, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

5.2. डीपीटी को यह निर्देश दिया जाता है कि कांडला भूमि की दर संरचना के संशोधन का प्रस्ताव 30 सितंबर, 2019 तक दायर कर दें।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./249/19]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th October, 2019

**No. TAMP/24/2014-KPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of rate structure of Kandla lands for categories 'A to G' of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/24/2014-KPT**

Deendayal Port Trust

- - -

Applicant

**ORDER****(Passed on this 10th day of October, 2019)**

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Kandla lands of DPT.

2. The lease rental for the Kandla lands of DPT was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The lease rental revised by this Authority was given retrospective effect from 1 January 2014 and validity was prescribed for a period of five years, i.e. up to 31 December 2018. The DPT was requested vide our letter dated 05 November 2018 to expedite filing of its proposal for revision of rentals of DPT land to avoid delay in notification of rates. Further, the existing rate structure for the Kandla lands for categories 'A to G' of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 29 March 2019 from the date of expiry till 30 June 2019 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

3.1. The DPT, vide its letter dated 31 July 2019 has submitted that the port has received the Land Valuation Report from the valuer and finalisation of rates applicable with effect from 01 January 2019 will take some more time. Hence, it has requested to extend the validity of existing rates for further 6 months i.e. 31 December 2019 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal to be filled by DPT, whichever is earlier, with 2% escalation. The revised rates to be proposed for revision of rate structure of Kandla land of DPT, is to be given retrospective effect from the date of expiry of last revision or rate structure of Kandla land of DPT i.e. 01 January 2019.

It has further stated that at present, provisional lease rent / compensation bills are issued to lessees, considering the 2% annual escalation over the rate prevailing during the year 2018.

3.2. Bringing out the above position, the DPT has requested this Authority to extend the validity of existing rates for further 6 months i.e. till 31 December 2019 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal to be filed by DPT, whichever is earlier, with 2% escalation.

3.3. Since the validity of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' has expired on 30 June 2019 and in view of the request made by the DPT, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Kandla lands for categories 'A to G' from the date of its expiry till 31 December 2019 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

3.4. The DPT vide our letter dated 14 August 2019 has already been requested to file its proposal for revision of rate structure for the Kandla lands for categories 'A to G' positively by 30 September 2019. The DPT is, therefore, directed to file its proposal within the stipulated date. Proposal from DPT is still awaited.

4.1. The Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government (based on which the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT has been fixed in November 2014) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in November 2014 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the MOS. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT.

4.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the

Kandla lands for categories 'A to G' based on a proposal filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

5.1. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT from the date of its expiry till 31 December 2019 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

5.2. The DPT is directed to file its proposal for revision of rate structure for Kandla land by 30 November 2019.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./249/19]